

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक सं.	62

**दिनांक 10 नवम्बर , 2017 को आयोजित 61 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

- दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को आयोजित 61 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |.
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक सं.	62

**पूर्व में आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट**

**राज्य सरकार से संबंधित मामले**

क्र.स.	से लंबित	विषय	झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान स्थिति
3.1.1	09.05.2013	नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।	पिछली SLBC की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जानकारी दी गई थी कि यह मामला अभी भी राज्य सरकार के विचारधीन है और इसमें जल्द ही प्रगति अपेक्षित है   नवीनतम सूचना अप्राप्त
3.1.2	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर सरकार की ओर से इसे राज्य में जल्द लागू कराये जाने का आश्वासन दिया गया था   नवीनतम सूचना अप्राप्त

**बैंक से संबंधित मामले Issues Pertaining To Banks**

बैंकों से संबंधित मामलों को इस बैठक से SLBC द्वारा ATR के रूप में discuss किये जाने का प्रावधान किया गया है | पिछली SLBC की बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उन मुद्दों को सभी संबंधित बैंको एवं LDMs को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए ATR के format में भेजा गया था, जिसका जबाब सभी LDMs एवं कुछ बैंको द्वारा प्रेषित किया गया है | इससे संबंधित compiled रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के पूर्व उन बैंको का उल्लेख जरूरी है जिन्होंने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया है | ये बैंक हैं-Andhra Bank, Axis Bank, Bandhan Bank, Dena Bank, Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, Indus Ind Bank, J & K Bank, Karnataka Bank, Karur Vaisya Bank, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank, South Indian Bank, Syndicate Bank और Yes Bank.

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	13.02.2018
बैठक सं.	62

**सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक ( KEY INDICATORS)**

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.12.2016	31.03.2017	31.12.2017	Bench Mark
1	Deposit	181734.26	186177.79	192003.77	
2	Credit	78827.49	81039.94	84018.21	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	26957.56	26141.95	32955.98	
4	Total Credit	105785.05	107181.89	116974.19	
5	CD Ratio	58.21	57.57	60.92	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	42619.46	43650.55	46176.52	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	54.07%	53.86%	54.96%	40
8	Agricultural Advances	13112.94	13704.11	13249.68	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	16.63%	16.91%	15.77%	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	18934.61	19753.78	21748.70	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	24.02%	24.37%	25.88%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	54.90%	55.69%	58.44%	
11	Advances to Weaker Sections	14862.26	15268.40	14699.00	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	18.85%	18.84%	17.50%	10
13	DRI Advances	49.66	51.15	40.96	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.06%	0.07%	0.05%	1
15	Advances to Women	11322.97	11706.69	10993.94	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	14.36%	14.45%	13.09%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5580.51	5679.66	5435.11	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	13.09%	13.01%	11.77%	15
19	Gross N.P.A	4642.51	4523.09	4992.87	
	Provision		1797.99	2377.64	
	Net NPA		2725.10	2615.23	
	Gross NPA Percentage	5.89%	5.58%	5.94%	
	Net NPA Percentage		3.36%	3.11%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1509	1513	1496	
	Semi-Urban	756	778	783	
	Urban	693	704	721	
	Total	2958	2995	3000	
21	ATM installed in Jharkhand	3449	3469	3536	

\*Annexure- V,

## पर्यवेक्षण

### जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 दिसम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर 2017 तक रुपये 10269.51 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 5.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

### ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रुपये 5190.72 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 6.58 प्रतिशत दर्ज की गई है।

### क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

कई तिमाहियों में CD ratio में लगातार दर्ज की गई गिरावट के बाद पिछली तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात 57.04 % से बढ़ कर, 58.78 % हो गया था। पुनः इस तिमाही में यह बढ़कर 60.92% हो गया है और कई तिमाहियों के पश्चात यह ratio राष्ट्रीय मानक 60% से ऊपर चला गया है। इसके लिए बैंक बधाई के पत्र हैं। यद्यपि बैंको का प्रयास सराहनीय है परंतु सितम्बर 2016 में 61.16% की CD ratio की तुलना में यह अभी भी कम है एवं सभी बैंकों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.34% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 54.96 % है जो राष्ट्रीय बैंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

### कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 दिसम्बर 2017 को कृषि अग्रिम रु. 13249.68 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 15.77 प्रतिशत है। पिछले वर्ष में कृषि ऋण कुल अग्रिम का 16.63 % था। यद्यपि पिछले एक साल में समग्र कृषि ऋण में रु. 136.44 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई है, परंतु वर्तमान में कृषि क्षेत्र का कुल अग्रिम मार्च 2017 की तुलना में लगभग रु 455 करोड़ कम है, जो की एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है। लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा।

### कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 दिसम्बर 2017 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रुपये 14699.00 करोड़ (17.50 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बैंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

### महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 दिसम्बर 2017 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रु. 10993.94 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 13.09 % है | यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है |

### अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 दिसम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5435.11 करोड़ है | यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 11.77% है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

### **31 दिसम्बर 2017 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात**

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15, दिनांक 01.07.14 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		31st December, 2016	31st December, 2017	
Aggregate Deposits		181734.26	192003.77	
CORE ADVANCES	78827.49		84018.21	
As per place of Utilization	22721.39		28079.37	
RIDF	4236.17		4876.61	
NET ADVANCES	105785.05		116974.19	
ऋण-जमा अनुपात		58.21		60.92

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक संख्या	62

**4.1 वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के तहत  
उपलब्धियों की समीक्षा : 31 दिसम्बर 2017 तक**

**समग्र स्थिति**

30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रु करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2016-17)	ACHIEVEMENT IN AFY 2016-17		ANNUAL TARGET (2017-18)	ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18	
	AMT	AMT.	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	7356.42	3032.59	41.22	7682.37	3216.97	41.87
MSME	6526.97	7420.13	113.68	7329.51	8270.37	112.83
OPS	3361.72	1929.23	57.38	3821.41	1869.82	48.93
Total Priority	17245.11	12381.95	71.80	18833.29	13357.16	70.92
Non Priority	10361.68	9525.43	91.92	8582.15	6896.90	80.36
<b>Total</b>	<b>27606.79</b>	<b>21907.38</b>	<b>79.35</b>	<b>27415.45</b>	<b>20254.06</b>	<b>73.87</b>

**टिप्पणियां :**

- ✚ वार्षिक ऋण योजना 2017-18 में पहली तीन तिमाहियों के दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 73.87 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से विशेष अनुरोध किया जा रहा है कि बाकी बचे 3 माह में इस वर्ष शत-प्रतिशत target प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाये।
- ✚ कृषि क्षेत्र में, वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत 09 महीनों में 3216.97 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण हुआ है, जो कि पिछले वित्त-वर्ष की पूरी अवधि के दौरान किये गए संवितरण से रु. 184.38 करोड़ अधिक है। परंतु कृषि क्षेत्र के कुल o/s में मार्च 2017 की तुलना में केवल रु 136.44 करोड़ की मामूली वृद्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है

कि कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का संवितरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन, मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके।

- ✚ MSME sector में बैंक की उपलब्धि को देखते हुए पहले भी यह चर्चा की गई है कि जिलों एवं बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर LDMS को ACP बनाते समय इन बातों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिए और MSME sector में ACP target में तर्कसंगत वृद्धि की जानी चाहिए।
- ✚ कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंकों द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-7(a) एवं 7(b) में दर्शाया गया है।
- ✚ 2017-18 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है।
- ✚ Agriculture Term Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7 में दिया गया है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक संख्या	62

## 5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

### 5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रु. 13249.68 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.77 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

### झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement During 2017-18		Outstanding In KCC Accounts AS OF 31.12.17	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	327729	1235.68	1209814	4791.93
Pvt. Banks	26323	141.99	22905	145.99
<b>Total</b>	<b>354052</b>	<b>1377.67</b>	<b>1232719</b>	<b>4937.92</b>
RRB	183432	630.07	365374	1294.99
Co-op Banks	1337	3.75	19251	31.82
<b>Total</b>	<b>538821</b>	<b>2011.49</b>	<b>1617344</b>	<b>6264.73</b>

( KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है )

- ❖ सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 31.12.2017 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1429021 eligible KCC खातों में से 1227149 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1212754 खातों में (98.83%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।

(विवरण पृष्ठ सं-8 (a) एवं 8 (b) में संलग्न है )

## 5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

### 5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र) (Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular	Outstanding position as at the end of			
		Dec 2016	Dec 2017		
(1)	(2)	(3)	(4)		
<b>MICRO &amp; SMALL ENTERPRISES</b>					
1	Micro Enterprises	Accounts	438	520	
		Amount	10394.54	12710.91	
2	Small Enterprises	Accounts	96	46	
		Amount	8540.07	9037.79	
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)	Accounts	534	566	
		Amount	18934.61	21748.70	
<b>MEDIUM ENTERPRISES</b>					
4.	Total of Medium Enterprises	Accounts	31	08	
		Amount	1900.47	1963.64	
<b>MSME</b>					
<b>TOTAL MSME ( PRIORITY SECTOR ADVANCES)</b>		Accounts	565	574	
		Amount	20835.08	23712.34	
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	54.90%	58.44%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	24.02%	25.88%

(MSME रिपोर्ट -annexure-9)

### COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE) (Position as on 31.12.2017)

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
342	14999.35	89	4226.92

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 9 में सलग्न है)

#### टिप्पणियां

- ✚ झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध दिसम्बर, 2017 में 58.44 % है।
- ✚ बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य में, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 3.42 लाख (लगभग) MSE ऋण खाते हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु

इनमें से केवल 0.89 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 26.02 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |

- कमोबेश सभी बैंकों का CGTMSE कवरेज प्रतिशत काफी कम है परंतु खास कर कुछ निजी बैंकों का CGTMSE कवरेज का प्रतिशत बिलकुल नगण्य है | अतः इन बैंकों एवं अन्य सभी दूसरे बैंकों से यह आग्रह है कि वे अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE कवरेज लेने का प्रयास करें |

## 5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | इसके अलावे Ministry of Textiles, GOI के निर्देशानुसार handloom weavers एवं artisans को दिये जाने वाले ऋण भी PMMY योजना के तहत आयेंगे | ध्यातव्य है कि crop loan, land improvement such as canals, irrigation, wells आदि को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है |

पूर्व में इस योजना के अंतर्गत सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में दिये गए ऋण का guarantee cover, CGTMSE scheme के अंतर्गत किया जा रहा था परंतु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

**प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.17 से 31.12.17 तक)**

(राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
Sanctioned	166061	524.88	44974	966.73	8734	649.43	219769	2141.04
Disbursed	165619	511.19	44813	910.61	8715	612.85	219147	2034.65

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में Micro Finance Agencies द्वारा लगभग 614094 खातों में रु 1278.08 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 614536 खातों में रु 1228.65 करोड़ की राशि वितरित की गई है | इस तरह MUDRA योजना के तहत राज्य में अब तक कुल 833683 खातों में रु 3263.31 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10 (a) एवं 10 (b) में सलग्न है)

## 5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 05.02.2018 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	SC/ST Beneficiaries	Loan Disbursed Amt (Rs in Cr)
392	341	51	33.67

सितम्बर 2017 तक केवल 91 लाभार्थियों को SUI ऋण योजना के तहत ऋण दिया गया था | यद्यपि इस sector में उपलब्धि अभी भी संतोषप्रद नहीं है, तथापि विगत 04 महीनों की उपलब्धि से यह परिलक्षित होता है कि बैंको द्वारा इस दिशा में किया गया प्रयास सराहनीय है | (रिपोर्ट पृष्ठ सं-11(a) एवं 11 (b) में सलग्न है)

## 5.3. शिक्षा ऋण Education loan

### शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

Particulars	As on 31.12.16	As on 31.12.17				Total As on 31.12.17	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSEMENT MADE DURING AFY 2017-18
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	63338	63521	515	854	3	64893	250.43	12133
Amount (In crore)	2511.54	2719.07	16.57	26.18	0.15	2761.97		467.33

(Annexure-10)

- उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 9.97 % के दर से वृद्धि हुई है | यद्यपि AFY 2017-18 की पहली तीन तिमाहियों में कुल 12133 छात्रों को रु. 467.33 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया है, पर इसमें और ज्यादा गति प्रदान करने की आवश्यकता है | उपस्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की शाखा स्तर पर ज्यादा शिक्षा-ऋण संवितरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दें |
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |

- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में )	संख्या	राशि (रु करोड़ में )
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2017-18)			12133	467.33
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	3406	156.30	3360	78.98
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	753	31.60	734	17.29

(रिपोर्ट संख्या -10 A)

#### 5.4- आवास ऋण

#### Performance of Banks under Housing loan Scheme

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 31.12.16	31.12.2017				Total Up to 31.12.17	GROWTH Y-O-Y IN HOUS. LOAN	Disbursements made in AFY 17-18
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	71046	69771	5236	567	45	75619	1441.39	13022
राशि	6270.69	7084.26	590.39	34.36	3.07	7712.08		1826.02

(रिपोर्ट -annexure-11)

#### 5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

##### 5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2017 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2016		% Share	31 दिसम्बर, 2017		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
42716.37	5580.51	13.06%	46176.52	5435.11	11.77%

(रिपोर्ट -annexure-13)

### 5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2017 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2016		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 दिसम्बर, 2017		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
78827.49	11322.97	14.36%	84018.21	10993.94	13.09%

(रिपोर्ट -annexure-13)

### 5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 दिसम्बर, 2017 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

31 दिसम्बर, 2016		DRI Percentage in Net Credit	31 दिसम्बर, 2017		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
78827.49	49.66	0.06	84018.21	40.96	0.05

(रिपोर्ट -annexure-12)

### 5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 दिसम्बर, 2017 समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु करोड़ में.)

31 दिसम्बर, 2016		Percentage	31 दिसम्बर, 2017		Percentage
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
78827.49	13412.05	17.01%	84018.21	12991.47	15.46%

(रिपोर्ट -annexure-13)

### 5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 159637 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 107590 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 824.63 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 554.28 करोड़ है |

(रिपोर्ट- Annexure-15)

NABARD से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 2017 तक झारखंड राज्य के NABARD द्वारा promoted/संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्नानुसार है:

	During Current FY 2017-18	Amt involved (Rs in Cr)	Upto 31.12.2017 since inception	Amt involved (Rs in Cr)
No. of SHGs saving linked	3305	13.28	53326	215.68
No. of SHGs credit linked (including SHGs of previous years)	4401	31.35	21584	159.37

### 5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

**एन आर एल एम की उपलब्धि (31 दिसम्बर, 2017 तक)** Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March'17	Addition during AFY-17-18	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	125	65	190
No of Villages	7038	4552	11590
Total No of SHGs supported by SRLM	80789	33180	113969
Total families supported by SRLM	979644	447859	1427503
No of SHG receiving R.F	37299	8521	45820
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	5566	1306	6872
No of SHG receiving CIF	27349	4166	31515
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	15706	2053	17759
No. of SHG credit linked with Banks	20321	37742	58063
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	10165	35242	45407

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 31.12.2017 तक यानि 09 महीनों में बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 31500 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS एवं NABARD के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या क्रमशः 37742 एवं 4401 यानि कुल 42143 बताई गई है | तीनों रिपोर्ट को बैंको, JSLPS एवं NABARD के अवलोकनार्थ सलंगन किया गया है | तीनों agencies से अनुरोध है कि वे आपस में ताल मेल कर अपनी-अपनी रिपोर्टिंग में आवश्यक सुधार कर सही आंकड़े SLBC को प्रेषित करें | (नाबाई एवं JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-14 (a) एवं 14 (f) में दिया गया है |)

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	13.02.2018
बैठक की संख्या	62

**वित्तीय समावेशन एवं  
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

**झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति**

**A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति**

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location )	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3699	479	Nil	3580	5129

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (a) & 15 (b)}

**B Online transaction करने वाले BC की स्थिति**

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
5784	5110	2423	1036	1651

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (c)}

**C. PMJDY के तहत 31.12.2017 तक खोले गए BSBD (Basic Savings Bank Deposit) खातों की स्थिति**

31.12.2017 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
8041547	3112207	11153755	8159076	9937798	7399987	6810430	5375740

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (d) & 15 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है )

यद्यपि पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 8159076 रुपये कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपये कार्ड में से केवल 6810430 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल 5375740 खातों में रुपये कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपये कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-16 (a) में दर्शाया गया है |

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :**

**दिनांक: 31.12.2017 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-**

PMJJBY		PMSBY		APY		
Total Enrolment	Premium Received (Rs. in Cr)	Total Enrolments	Premium Received (Rs. in Cr)	Target for FY 2017-18	Total Enrolments during 17-18	% achievement during FY 17-18
510306	16.84	3621431	4.35	195290	93370	48%

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-16 (b) सलंगन है)

**वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का  
अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गाँवों में बैंकिंग शाखा खोलने संबंधित रोडमैप**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आवादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमें से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था |

आरबीआई के बैंकिंग आउटलेट के संबंध में नए दिशानिर्देश बैविवि. बीसी.बीएपीडी.सं.69/22.01.001/2016-17 दिनांक 18 मई 2017 के अनुसार “ किसी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (डीएससीबी) लघु वित्त बैंक (पीबी) और भुगतान बैंक (एसएफबी) के लिए **बैंकिंग आउटलेट**, एक नियत स्थल पर सेवा सुपुर्दगी इकाई है, जिसे बैंक के स्टाफ अथवा उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है, जहां सप्ताह में **कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे** के लिए जमाराशियां स्वीकार करने, चेकों का नकदीकरण आहरण /अथवा पैसा उधार देने की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं | इसमें बैंक के नाम और उससे प्राप्त प्राधिकार के साथ नियंत्रक प्राधिकारियों और शिकायत निवारण प्रणाली के संपर्क ब्योरे सहित कारोबार समय दर्शित किया जाना चाहिए |

पिछली SLBC की बैठक तक इस निर्देश के अनुसार निर्धारित 137 में 132 गाँव में बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके थे। बाकी बचे 5 गाँवों में शाखा का खोला जाना /BC की नियुक्ति का निर्देश संबंधित बैंकों को दिया गया था | SLBC द्वारा बार-बार आग्रह के बावजूद 01 जगह पर यह स्थिति अभी भी यथावत है | Vijaya Bank के द्वारा Chanho Block के Patrattu गाँव में न तो बैंक की शाखा खोली गई है और न ही BC की नियुक्ति की गई है |

(वर्तमान वस्तुस्थिति पृष्ठ संख्या- 17 (a) में संलग्न है)

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक सं	62

**एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय**

**गैर निष्पादनीय आस्तियां**

राज्य के बैंकों में दी 31 दिसम्बर 2017 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.12.16	31.03.17	31.12.17	Growth over last FY	% Growth (over last FY)
Advances	78827.49	81039.94	84018.21	2978.27	3.67%
Gross NPA	4642.51	4523.09	4992.87	469.78	10.38%
Provision		1797.99	2377.64	579.65	32.23%
Net N.P.A		2725.10	2615.23	(-)109.87	
Percentage of Gross NPA	5.89 %	5.58 %	5.94%	0.36%	
percentage of Net NPA		3.36 %	3.11%	(-)0.25%	

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है । रु 4992.87 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.94 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है ।

विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलगनक के रूप में दर्शाये गए हैं ।

**सर्टिफिकेट केस का स्थिति**

दिनांक 31 दिसम्बर 2017 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[ राशि करोड़ में ]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases dispoed during last Qtr.		status as on 31.12.2017	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
108814	354.64	4957	50.78	3453	44.73	110318	360.69

(रिपोर्ट- annexure-20)

**DRT केस की स्थिति**

दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[ राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 31.12.17	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1976	839.82	315	27.92	224	118.26	2067	749.48

(रिपोर्ट- annexure-21)

**SARFAESI केस की स्थिति**

दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

जिला का नाम	Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों के पास भेजे गए cases की संख्या	Amt involved (Rs in Cr)
बोकारो	78	66.60
देवघर	06	1.80
धनबाद	25	11.57
पूर्वी सिंहभूम	63	35.92
गिरिडीह	02	0.18
गोड्डा	01	0.06
हजारीबाग	13	2.99
खूंटी	01	0.20
कोडरमा	01	0.22
लातेहार	02	3.17
लोहरदगा	05	0.47
पलामू	02	0.15
रामगढ़	04	1.21
रांची	29	28.48
सराइकेला	14	51.24
सिमडेगा	02	0.33
पश्चिमी सिंहभूम	05	3.52
<b>कुल</b>	<b>253</b>	<b>208.11</b>

बैंक का नाम	Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों के पास भेजे गए cases की संख्या	Amt involved (Rs in Cr)
Allahabad Bank	36	41.18
Bank of India	08	6.34
Canara Bank	16	13.49
Central Bank of India	17	12.84
Corporation Bank	01	0.68
Dena Bank	04	1.56
ICICI Bank	12	1.58
Indian Bank	02	0.44
Indian Overseas Bank	01	5.97
Punjab National Bank	07	40.10
UCO Bank	18	23.56
Union Bank	27	15.06
United Bank	104	45.31
<b>Total</b>	<b>253</b>	<b>208.11</b>

विभिन्न बैंको से प्राप्त Physical possession के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों के पास भेजे गए cases का जिलावार ब्यौरा रिपोर्ट संख्या -20 (a) से 20 (e) तक दर्शाया गया है ।

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक सं	62

## सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

### 8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.01.2018 तक की स्थिति इस प्रकार है-

( राशि करोड़ में )

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
NO	MM Involved	NO	MM Involved	NO	MM	NO	MM
9391	236.22	1336	29.77	4819	115.39	3286	88.88

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.01.2018 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है )

### 8.2 NULM एवं PMAY

शहरी विकास विभाग के पोर्टल से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-21 (a) में एवं PMAY से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-21 (b) & 21 (c) में दर्शायी गई है।

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	13.02.2018
बैठक संख्या	62

### RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : ( as of 31.12.2017)  
झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा है |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

#### AFY 17-18 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -580 ; प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	-	17370
उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -383 प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	-	11066
{State Director, RSETI से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-22 (a)}		

#### RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन	-	04
भवन निर्माण कार्य सम्पूर्ण/finishing work जारी	-	07
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	-	13
भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी	-	01
(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-22 (b) में संलग्न है )		

#### RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2016-17 के दौरान		AFY 2017-18 के दौरान	
कुल प्रशिक्षणार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षणार्थी	Credit Linked
19605	2855	11066	1879

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-22 (c) एवं 22 (d) पर उपलब्ध है )

## वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

**झारखण्ड ग्रामीण बैंक** - 15 केन्द्र ; **वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है ।

### अक्टूबर-दिसम्बर, 2017 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	996
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	1829
कुल	2825

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-23 (a) एवं 23 (b) पर उपलब्ध है}

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	13.02.2018
बैठक संख्या	62

## एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

### एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1) प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2) प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या	1) कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2) नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	08.02.2018

			डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां		
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	09.02.2018
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि ) 5) एसबीआई ( आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	11.01.2018

			<p>6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )</p> <p>7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )</p> <p>8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि )</p>		
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<p>1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ.</p> <p>2) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>3) नाबार्ड</p> <p>4) भारतीय स्टेट बैंक</p> <p>5 ) बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>6) पंजाब नेशनल बैंक</p> <p>7) झारखंड ग्रामीण बैंक</p> <p>8) केनरा बैंक</p> <p>9 )यूनियन बैंक</p>	<p>1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात</p> <p>2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति</p> <p>3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास</p>	09.02.2018
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<p>1) संस्थागत वित्त विभाग</p> <p>2) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>3) नाबार्ड</p> <p>4) निदेशक, उद्योग</p> <p>5) आईसीआईसीआई बैंक</p> <p>6) केनरा बैंक</p> <p>7) पंजाब नेशनल बैंक</p> <p>8) बैंक ऑफ इंडिया</p> <p>9) भारतीय स्टेट बैंक</p>	<p>1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें</p> <p>2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)</p>	09.02.2018

6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक-एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) सचिव, ग्रामीण विकास</li> <li>2) सचिव, सहकारी</li> <li>3) सचिव, राजस्व</li> <li>4) सचिव, कृषि</li> <li>5) सचिव, योजना</li> <li>6) भारतीय स्टेट बैंक</li> <li>7) बैंक ऑफ इंडिया</li> <li>8) इलाहाबाद बैंक</li> <li>9) भारतीय रिजर्व बैंक</li> </ol>	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	<b>02.02.2015</b>
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक-बीओआई	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) सचिव, ग्रामीण विकास</li> <li>2) सचिव, संस्थागत वित्त</li> <li>3) सचिव, उद्योग</li> <li>4) भारतीय स्टेट बैंक</li> <li>5) बैंक ऑफ इंडिया</li> <li>6) इलाहाबाद बैंक</li> </ol>	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	12.12.2017 को RBI Empowered Committee on MSME की 36वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक-एसबीआई	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) सचिव, शहरी विकास</li> <li>2) सचिव, वित्त</li> <li>3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि</li> <li>4) भारतीय स्टेट बैंक</li> <li>5) बैंक ऑफ इंडिया</li> <li>6) इलाहाबाद बैंक</li> <li>7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष</li> </ol>	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	<b>07.11.2017</b>
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास</li> <li>2) सचिव, वित्त</li> <li>3) भारतीय रिजर्व बैंक</li> <li>4) एसएलबीसी</li> <li>5) भारतीय स्टेट बैंक</li> <li>6) बैंक ऑफ इंडिया</li> </ol>	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	<b>09.02.2018</b>

			<p>7) केनरा बैंक</p> <p>8) पी.एन.बी.</p> <p>9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक</p> <p>10) नाबार्ड</p>		
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	<p>1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास</p> <p>2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ</p> <p>3) भारतीय रिजर्व बैंक</p> <p>4) एसएलबीसी</p> <p>5) नाबार्ड</p> <p>6) भारतीय स्टेट बैंक</p> <p>7) केनरा बैंक</p> <p>8) पी.एन.बी.</p> <p>9) राज्य निदेशक, RSETI</p>	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	<b>09.02.2018</b>

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	13.02.2018
बैठक सं.	62

## विविध कार्यसूची

1. वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 25.09.2017 से 17.10.2017 तक देश के 50 विभिन्न स्थानों पर "मुद्रा प्रोत्साहन अभियान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके तहत रांची के मोरहाबादी मैदान में दिनांक 12.10.2017 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्र सरकार की ओर से माननीय राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन विभाग, श्री जयंत सिन्हा जी मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन SLBC, झारखण्ड के द्वारा किया गया था एवं DFS के निर्देशानुसार कार्यक्रम के आयोजन में LIC द्वारा दी गई रु 10.00 लाख की सहयोग राशि के अतिरिक्त किये गए व्यय के आधार पर सभी प्रतिभागी बैंकों से रु 77400/- का contribution की मांग की गई थी। बैंकों के contribution की बात SLBC द्वारा कार्यक्रम के पूर्व में होने वाली बैठकों एवं mail के द्वारा सभी बैंकों को दी गई थी। लगभग 04 माह बीत जाने एवं बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह किये जाने के बावजूद 08 बैंक Axis Bank, ICICI Bank, UCO, Corporation, VGB, BOB, Vijaya और IOB ने अब तक अपना contribution SLBC को प्रेषित नहीं किया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस forum के माध्यम से हम इन बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से यह आग्रह करते हैं कि यह राशि SLBC को दिनांक 28.02.2018 के पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

**(Action: उपर्युक्त नामित सभी बैंक)**

2. दिनांक 25.01.2018 को झारखण्ड राज्य के दुमका जिले में संथाल परगना के 06 जिलों के लिए हुए विशेष SLBC की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी बैंकों द्वारा संथाल परगना में CD ratio को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि इन जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर CD ratio में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करें।

**(Action: संथाल परगना जिलों में अवस्थित सभी बैंक)**

3. DFS द्वारा दिनांक 15.12.2017 एवं 19.12.2017 को भेजे गए मेल में पूरे झारखण्ड राज्य में जिलावार 5 KM के दायरे में 2764 गाँवों को चिन्हित किया गया है और वहाँ बैंकिंग outlet की जानकारी मांगी गई है कि वे गाँव बैंक शाखा अथवा BC से covered हैं या नहीं? पुनः दिनांक 11.01.2018 को भेजे गए communication में BC के KO code, location address,

mobile no तथा “क्या वे BC RBI के नये मानदंडों के अनुसार fixed location माने जा सकते हैं “ जैसी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है | अभी तक केवल 17 LDMs द्वारा इसका रिपोर्ट SLBC को प्रेषित किया गया है | दुमका, पूर्वी सिंघभुम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज एवं सिमडेगा LDMs द्वारा यह रिपोर्ट नहीं दिया गया है | इस रिपोर्ट से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ज्यादातर जगहों पर RBI के मानदंडों के अनुसार fixed location BC नहीं है | SHG पर SLBC sub committee की दिनांक 09.02.2018 को हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि चूँकि अभी कई जगहों पर BC की नियुक्ति करनी पड़ेगी तो बैंकों द्वारा WSHG के members को BC agent के रूप में नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जाये | (अद्यतन प्रतिवेदन सलंगन)

(Action: सभी बैंक एवं LDMs)

4. DFS के पत्रांक 20/57/2010-FI दिनांक 22.11.2017 के द्वारा LWE जिलों में banking services के expansion के लिए झारखण्ड राज्य के पलामू एवं छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिलों को pilot जिलों के रूप में identify किया गया और वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए banking outlets establish किये जाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया था, ताकि इन जिलों की प्रगति के आधार पर अन्य LWE जिलों में इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके | इस सम्बन्ध में पलामू जिले में जिले के अधिकारियों द्वारा बैंको के साथ बैठक कर 06 स्थानों को चिन्हित कर बैंक की शाखाएँ खोले जाने का प्रस्ताव आया है | इन 06 स्थानों पर PNB, BOI, Andhra Bank एवं SBI द्वारा शाखा खोला जाना है | SLBC द्वारा दिनांक 29.01.2018 को इस सम्बन्ध में इन बैंको एवं पलामू जिले के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चिन्हित स्थानों पर बैंक शाखा खोलने हेतु संबंधित बैंक अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है | इन बैंको से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में हुई प्रगति SLBC को अविलम्ब प्रेषित करें ताकि इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा MHA एवं DFS को दिया जा सके |

Sr No	Identified locations/blocks	Proposed bank's name	Proposed place where branch may be opened
1	Naudiha Bazar	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
2	Pipra	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
3	Pandu	Bank of India	Block Office (under Construction)
4	Lalgarh Bihar	Andhra Bank	Railway Station
5	Ramgarh	State Bank of India	Panchayat Bhavan, Ramgarh
6	Untari Road	State Bank of India	Newly built Block Office premises

(Action: PNB, BOI, Andhra Bank एवं SBI)

5. DFS के पत्रांक 20/57/2010-FI Vol. VIII दिनांक 19.01.2018 के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित LWE जिलों में कुछ गाँवों को चिन्हित कर Integrated Development Hubs/ Centres के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय जनता को विभिन्न विकास योजनाओं यथा PMJDY, PMMY, SUI, PMJJBY, PMSBY और APY के लाभों की जानकारी पहुँचाने

के लिए awareness camp करने का निर्देश दिया गया है | झारखण्ड राज्य में कुल 322 गाँवों को चिन्हित किया गया है | इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला,पूर्वी सिंघभुम, पश्चिमी सिंघभुम, पलामू, लातेहार, गढ़वा,बोकारो, हजारीबाग, चतरा , गिरिडीह, रामगढ,एवं दुमका के LDMs को दिनांक 20.01.2018 को मेल के द्वारा सूचित किया गया था और इनसे ATR माँगा गया था, परंतु अभी तक किसी भी LDM ने ATR प्रेषित नहीं किया है | चूँकि DFS के साथ होनेवाली साप्ताहिक VC में इससे संबंधित प्रगति की जानकारी देनी होती है, अतः इन LDMs से आग्रह है कि वे इन 322 गाँवों में awareness camp organise कर इसकी जानकारी SLBC को अविलम्ब उपलब्ध करा दे |

(Action: सभी LDMs)

6. दिनांक 07.02.2018 को DFS ने सभी SLBC को यह निर्देश दिया है कि APY को अलग agenda के रूप में रख कर इस पर विस्तृत विचार किया जाये और बैंको के performance की प्रगति पर गहन ध्यान दिया जाये | PFRDA द्वारा उपलब्ध कराये गए APY से संबंधित आंकड़े सलग्न है | जिन बैंको का enrollment प्रतिशत 50% से कम है, उनके नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि मार्च 2018 तक इसमें अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करें |

(Action: सभी बैंक)

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	13.02.2018
बैठक सं	62

### Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आहवाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं | इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 31.12.2017 तक राज्य में कुल 28203 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था | यद्पि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है | इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 3.54 लाख credit card, 1.54 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 20 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है |
- {प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-32 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	13.02.2018
बैठक सं	62

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

**63वीं SLBC बैठक की प्रस्तावित तिथि : 11 मई 2018**